Toppersnotes
Unleash the topper in you

IAS

संघ लोक सेवा आयोग

सामान्य अध्ययन

पेपर - 3 || भाग - 1

SIERRA INNOVATIONS

विषय-सूची

1.	मुद्रास्फीति	1
2.	उदारीकरण	7
3.	IT की नीति	8
4.	राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद	9
5.	लोक वित्त	25
6.	भारत सरकार के खर्चे	33
7.	वित्त आयोग	37
8.	मूल्य संवर्द्धन कर	39
9.	वस्तु एवं सेवा कर	40
10.	कर टालना	43
11.	भारतीय रिजर्व बैंक	45
12.	गैर निष्पादित संपत्ति	53
13.	वित्तीय समावेश	58
14.	वित्त बाजार	61
15.	भारत के मुद्रा बाजार	62
16.	भारत के इक्विटी व्यापार	63
17.	मुद्रास्फीति और भविष्य के बाजार	71
18.	स्टार्टअप	73
19.	भारत के विदेशिक क्षेत्र	76
20.	मुद्रा की परिवर्तनीयता	80
21.	विदेशी व्यापार नीति	81
22.	विनिमय दर	85
23.	क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी	89

24.	टोटलाइजेशन (समझौता)	89
25.	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन	90
26.	समावेशी विकास	100
27.	कृषि सब्सिडियों का विकास	104
28.	न्यूनतम समर्थन मूल्य	110
29.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	118
30.	कृषि विपणन प्रणाली	123
31.	पशुपालन का अर्थशास्त्र	131
32.	भूमि सुधार	135
33.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	143
34.	सरकारी बजट	149
35.	कालाधन/ कर चोरी	153
36.	धन-शोधन	158
37.	आधारभूत संरचना	163
38.	निवेश मॉडल	170
39.	बौद्धिक संपदा अधिकार	173
40.	आर्थिक उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	178
41.	औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक नीति पर नीति पर इसका प्रभाव	185
42.	गरीबी	188
43.	बेरोजगारी	194
44.	खाद्य सुरक्षा	198

मुद्रा स्फीति (Inflation)

प्रस्तावना :-

मुद्रास्फीति एक ऐसी आर्थिक स्थिति होती है, जिसमें चयनित वस्तुओं की कीमत स्तर (Price Level) बढ़ने लगता है।

मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा होती है क्योंकि इससे न केवल देश का जीडीपी व रोजगार प्रभावित होते हैं बल्कि इससे सामाजिक न्याय की संकल्पना पर भी प्रभाव पड़ता है।

मुद्रास्फीति का मापन :-

मुद्रास्फीति को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है जैसे की थोक मूल्य सूचकांक WPI (Whole Sale Price Index)] उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI(Consumer Price Index)] उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI(Producer Price Index)।

कीमत सूचकांकों का प्रयोग करने से मुद्रास्फीति की गणना करना आसान हो जाता है। कीमतों से कीमत सूचकांक की ओर जाने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है -

कीमत सूचकांक = $\frac{P_1}{P_0}$ X 100

P_1= चालू मूल्य या प्रचलित मूल्य (Current Price)

P_0= आधार मूल्य (Base Price)

भारत में मुद्रास्फीति की गणना :-

भारत सरकार द्वारा MPI को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इस संदर्भ में Office of Economic Advisor (Ministry of Commerce and Industry) द्वारा प्रत्येक माह में मुद्रास्फीति के आँकड़े जारी किए जाते हैं।

KBI द्वारा मुद्रास्फीति के संदर्भ में कोई भी निर्णय करने तथा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण IT (Inflation Targeting) की नीति को संचालित करने के लिए CPI-NS (New Series) का प्रयोग किया जाता हैA CPI-NS को CSO (Central Statistics Office) द्वारा तैयार किया जाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को मुद्रास्फीति का बेहतर मानदंड माना जाता है इसके दो मुख्य कारण निम्न कारण -

1. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है जबकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में सेवाओं की भूमिका होती। उपर्युक्त के विपरीत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में सेवाओं का समाविष्ट होता है।

2. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) थोक स्तर की कीमतों को ध्यान में रखता है जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) उपभोक्ता स्तर की कीमतों पर ध्यान रखता है।

   थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की उपर्युक्त कमियों के मद्देनजर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रयोग को वरीयता दी जा रही है। यही कारण है कि IT की पॉलिसी में CPI&Ns को ध्यान में रखा गया।

भारत में मुद्रास्फीति की दर निकालने के लिए Point to Point अथवा Year on Year विधि का प्रयोग किया जाता है ।

इस विधि के अंतर्गत यदि दिसंबर 2016 के लिए मुद्रास्फीति की दर की गणना करनी है, तो दिसंबर 2015 के थोक मूल्य सूचकांक (WPI)/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के मूल्य के साथ की जाएगी और प्रतिशत परिवर्तन निकाला जाएगा । यह प्रतिशत परिवर्तन ही दिसंबर 2016 के लिए मुद्रास्फीति की दर होगी ।

जैसे :-

CPI-Ns-2012

टमाटर–20

2016	2015
जनवरी	जनवरी
फरवरी	फरवरी
.	.
.	.
.	.
दिसम्बर 440	दिसम्बर 400

उपर्युक्त चित्र को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि दिसंबर 2016 की मुद्रास्फीति की दर $\frac{40}{400} \times 100$ होगी ।

$$\frac{40}{400} \times 100 =$$

10%

दिसम्बर **2016**	दिसम्बर **2015**
440	400 → $\frac{40}{400} \times 100 =$
132.8	127.9 → $\frac{4.9}{1000} \times 100 = 3.8\%$

कभी–कभी मुद्रास्फीति की दर गणितीय रूप से अत्यधिक ऊँची अथवा कम दिखाई देती है, इसे आधार प्रभाव (Base Effect) का जाता है ।

आधार प्रभाव (Base Effect) उन वस्तुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनकी कीमतें घटती–बढ़ती रहती हैं, भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित दो प्रकार की वस्तुएँ आधार प्रभाव (Base Effect) उत्पन्न करती है –

1- खाद्य वस्तुएँ ¼Food Articles)
2- ईंधन से जुडी वस्तुएँ जैसे कि क्रूड ऑयल

भारत में मानसून आदि कारणों से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार–चढाव उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार OPEC आदि समूह कच्चे तेल की आपूर्ति में परिवर्तन करके इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ।

इसके अलावा भारतीय रू. की विनिमय दर में होने वाले बदलाव भी कच्चे तेल की घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालते हैं ।

उत्पत्ति **(Production) :-**

2001-02 → 100

2002-03 -7.2% → 93

2003-04 10% → 100

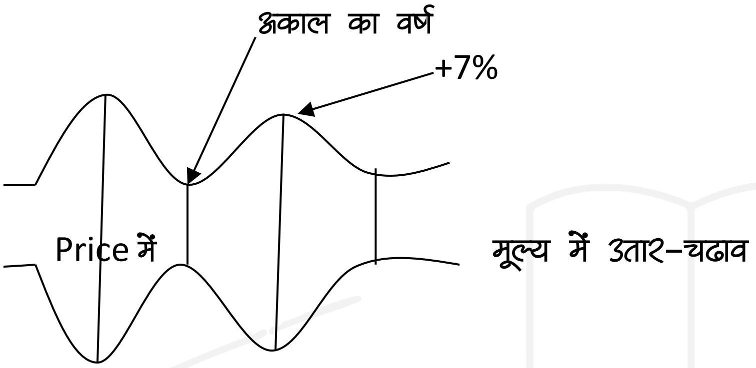

मूल्य (Price)

आधार प्रभाव (Base effect)
2012 = 100
टमाटर (Tomato) = 20

दिसम्बर,16

₹ 80 = $\frac{80}{20} \times 100$ = 400

दिसम्बर,15

₹ 80 = $\frac{80}{20} \times 100$ = 400

0% मुद्रास्फीति

कोर मुद्रास्फीति v/s हेडलाइन मुद्रास्फीति (Core inflation v/s Head Lines Inflation)

आधार प्रभाव की समस्या के निराकरण के लिए मुद्रास्फीति की गणना से खाद्य तथा ईंधन से जुडी वस्तुओं को हटा दिया जाता है । इन्हें हटाने के बाद प्राप्त की गई मुद्रास्फीति की दर को कोर मुद्रास्फीति कहते हैं । उपर्युक्त के विपरीत हेडलाइन मुद्रास्फीति के मामले में इन वस्तुओं को नहीं हटाया जाता है ।

आर.बी.आई. किसी भी मौद्रिक निर्णय हेतु कोर मुद्रास्फीति पर विशेष रूप से ध्यान देता है, जबकि सामान्य जनता के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति के आँकडे जारी किए जाते हैं ।

माँगजन्य मुद्रास्फीति v/s लागतजन्य मुद्रास्फीति (Demand Pull Inflation v/s Cost-Push Inflation)

जब मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने का मुख्य कारण समग्र माँग (Aggregate demand) अधिक हो तो ऐसी मुद्रास्फीति को माँगजन्य मुद्रास्फीति कहते हैं । समग्र माँग के अंतर्गत ब्याज दरों का कम होना, तरलता

अथवा मुद्रा का प्रसार, सरकारी खर्च का अधिक होना, निर्यातों का बढना, उपभोग का बढना आदि कारकों को शामिल किया जा सकता है ।

<u>लागतजन्य मुद्रास्फीति</u> **<u>(Cost-Push Inflation)</u>**

Cost-Push inflation में वस्तुओं की कीमतों के बढने का कारण समग्र माँग में अधिकता नहीं होती है । इसका मुख्य कारण उत्पादन की लागतों का ऊँचा होना होता है । इसके अलावा भारत जैसे राष्ट्रों में निम्न स्थितियाँ देखने को मिलती हैं –

1- Supply bottlenecks - वस्तुओं की आपूर्ति में विभिन्न प्रकार की बाधाएँ होती हैं ।
2- Supply inelasticity - बढी हुई कीमत पर आपूर्ति अधिक नहीं बढ पाती है ।

जैसे :- नमक

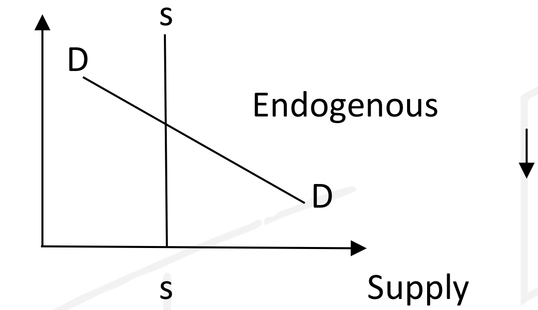

3. <u>Exogenous Supply Shocks</u> -
बाह्य आपूर्ति के झटके जैसे मानसून का कम रह जाना] Oil Shocks (1970) आदि ।

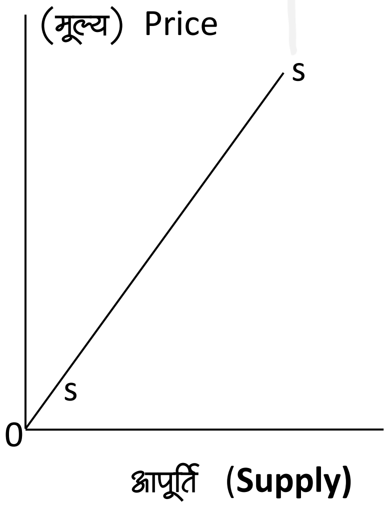

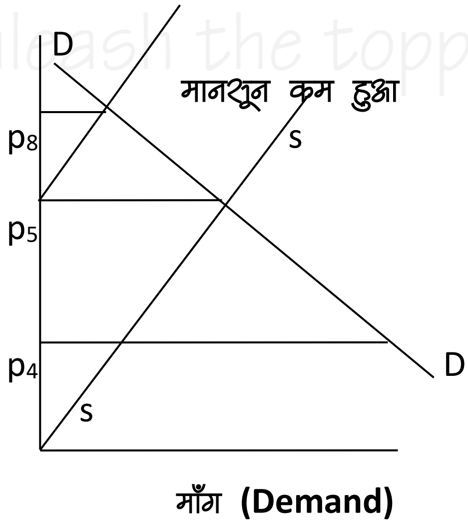

इस प्रकार भारत की मुद्रा स्फीति लागतजन्य प्रकार की है लेकिन यह देखा गया है या देखा जाता है कि भारत में अधिकांश मामलों में माँग प्रबन्धन पॉलिसी को लागू किया जाता है, जिसमें ब्याज दरों को बढाया जाता है तथा तरलता को नियंत्रित किया जाता है, इससे तत्कालिक रूप से लाभ तो होता है लेकिन स्थाई समाधान नहीं मिल पाता है ।

4- <u>बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति (**Growth, Unemployment And Inflations**)</u> **:-**

यह ध्यान देने योग्य है कि जी.डी.पी. की वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति के मध्य सकारात्मक संबंध पाया गया है । इसका निहितार्थ यह हुआ कि यदि जी.डी.पी. की वृद्धि दर बढती है, तो मुद्रास्फीति की दर बढेगी । इसी प्रकार बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में विपरीत संबंध पाया गया है, इसका निहितार्थ यह हुआ कि यदि बेरोजगारी की दर को कम किया जाता है, तो मुद्रास्फीति की दर बढेगी ।

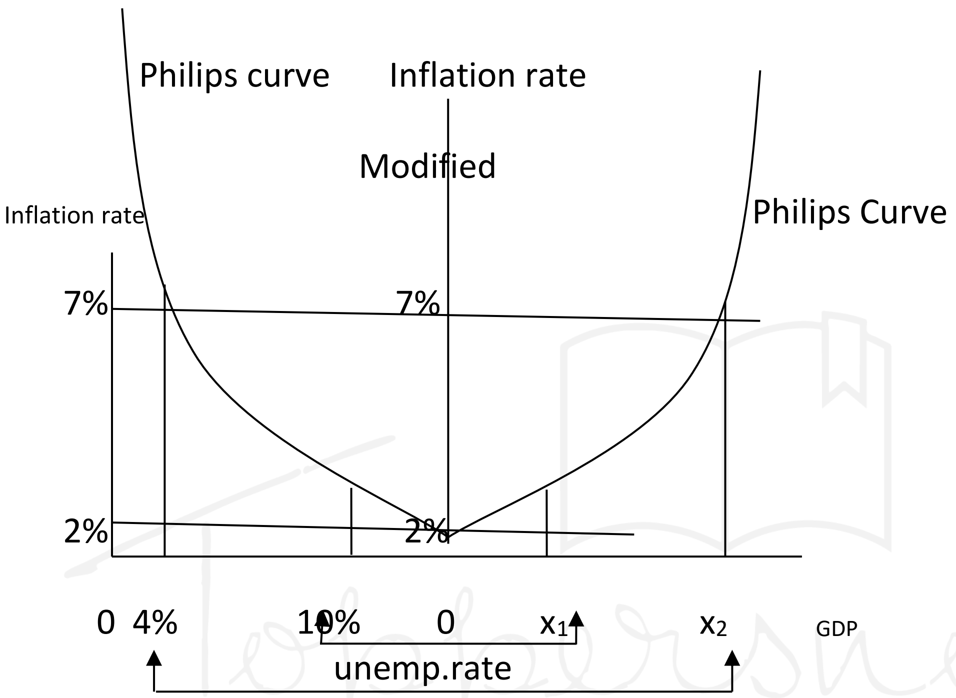

उपर्युक्त चित्र के अनुसार शुरुआत में बेरोजगारी की दर 10 प्रतिशत है । यदि बेरोजगारी की दर को कम करना है तो जीडीपी को बढावा देना होगा । इस संदर्भ में ब्याज दरों को कम किया जाएगा, तरलता का विस्तार, टैक्स में छूट दे दी जाएगी तथा उत्पादकों को निवेश सब्सिडी दी जायेगी ।

इसके परिणामस्वरूप उत्पादन को बढावा मिलेगा, इससे श्रमिकों की माँग बढेगी जिससे मजदूरियाँ बढने लगेगीं जिसके फलस्वरूप मंहगाई की मार आने लगेगी यदि मंहगाई की मार के साथ श्रमिकों की उत्पादकता नहीं बढती तो वस्तुएँ महंगी हो जाएगी जिससे मुद्रास्फीति का स्तर ऊँचा हो जाएगा ।

<u>थोक मूल्य सूचकांक (**WPI**)</u> :-

- यह सूचकांक थोक मूल्यों पर आधारित है ।
- 2014 तक भारत में इसे मुद्रास्फीति के मापन में प्रयोग में लाया जाता था ।
- यह सूचकांक उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ।
- थोक मूल्य सूचकांक केवल वस्तुओं पर आधारित होता है ।
- निम्न प्रकार के थोक मूल्य सूचकांक घोषित किये जाते हैं ।

  (1) <u>प्राथमिक वस्तुओं का (थोक मूल्य सूचकांक)</u>:-

  इसमें खाद्य पद्धार्थों को शामिल किया जाता है । इसमें 117 वस्तुएँ शामिल हैं ।

(2) ईंधन का थोक मूल्य सूचकांक :- इसमें 16 वस्तुएँ शामिल की जाती हैं ।

(3) विनिर्मित वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक :- इसमें 564 विनिर्मित वस्तुएँ शामिल की जाती हैं ।

(4) मुख्य थोक मूल्य सूचकांक :- उपरोक्त सभी को सम्मिलित करते हुए मुख्य WPI ज्ञात किया जाता है ।

- इसमें 697 वस्तुएं शामिल की जाती है ।
- WPI की घोषणा प्रत्येक महीने की 14 तारीख को की जाती है ।
- WPI का वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(CPI)** :-

- यह उपभोक्ता मूल्यों पर आधारित सूचकांक है ।
- 2014 ई. में इसे भारत का मुख्य सूचकांक घोषित किया गया ।
- वर्तमान में आर.बी.आई. द्वारा मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है ।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं के साथ सेवाओं में होने वाले परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है ।
- इसकी घोषणा MOSPI, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन CSO (Central Statistics Office) द्वारा की जाती है ।
- इसकी गणना हेतु वस्तु एवं सेवाओं के समूह को आधार बनाया जाता है ।
- इसे वस्तु और सेवाओं की बॉस्केट कहा जाता है ।
- ग्रामीण क्षेत्र की बॉस्केट में 448 व शहरी क्षेत्र की बॉस्केट में 960 वस्तु और सेवाएँ शामिल की जाती है ।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात किया जाता है ।
- इनके आधार पर एक सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घोषित किया जाता है ।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की घोषणा प्रत्येक महीने की 11 तारीख को की जाती है ।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थो की 60% भारांश दिया जाता है ।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की घोषणा की जाती है । जैसे- औद्योगिक श्रम का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता व मनरेगा मजदूरी आदि ज्ञात की जाती है ।
- विश्व के लगभग 157 देशों में इसे अपनाया जाता है ।
- इसका आधार वर्ष 2012 ई. है ।

उदारीकरण

उदारीकरण शब्द की उत्पत्ति राजनीतिक विचारधारा 'उदारवाद' से हुई है, जोकि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई थी। (यह वस्तुतः पिछली तीन शताब्दियों में विकसित हुई थी।)
उदारीकरण शब्द का अर्थव्यवस्था में वहीं अर्थ होगा, जोकि इसके मूल शब्द उदारवाद का है। अर्थव्यवस्था में बाजार समर्थक या पूँजीवादी समर्थक की ओर आर्थिक नीतियों का झुकाव ही उदारीकरण है। हमनें 1970 के दशक में इसे सम्पूर्ण यूरो-अमरिका और विशेषकर 1980 के दशक में होते हुए देखा है इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण 1980 दशक मध्य में चीन है। जब इसने 'खुले द्वार की नीति' की घोषणा की थी। यद्यपि चीन में आज भी कुछ विशिष्ट उदारवादी लक्षणों का अभाव है। जैसे – के लिए व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रणाली इत्यादि हैं। फिर भी चीन को उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा गया।

अन्य शब्दों में, उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने के प्रयास किये जाये, जिससे देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें।

- उदारीकरण का मतलब होता है कि व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करना जिससे व्यवसायी तथा उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पडे।
- उदारीकरण व्यापारिक दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किया है और सभी देशों के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान किये है।
- उदारीकरण नई औद्योगिक नीति का वह परिणाम है जो 'लाइसेंस प्रणाली' को समाप्त कर देता है। तो इस तरह से हम कह सकते है कि सरकार द्वारा व्यापार नीति को उदार बनाना जो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह पर टैरिफ, सब्सिडी और अन्य प्रतिबंधों को हटा रहा है, उदारीकरण के नाम जाना जाता है।

उदारीकरण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है :-

1. लाइसेंसिंग प्रणाली को न्यूनतम तथा सरल बनाना।
2. सरकारी नियंत्रणों के स्थान पर बाजार शक्तियों को प्रोत्साहित करना।
3. स्कन्ध विपणित क्रियाओं को नियमित करना।
4. वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन पर लगी बाधाओं को हटाना।
5. नवीन उद्योगों की स्थापना को स्वतंत्रता देना।
6. इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना अथवा न्यूनतम करना।
7. वस्तुओं की कीमत का निर्धारण उत्पादकों/निर्माताओं द्वारा किया जाना।
8. आयात नीति को सरल बनाना।
9. उत्पादों के वितरण पर लगी रोकों को हटाना।

आई.टी. की नीति

प्रस्तावना :-

भारत में इस नीति को हाल ही में लागू किया गया है । इसे उर्जित पटेल समिति तथा वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग FSLR (Financial Sector Legislative Reforms Commission) की सिफारिशों पर लागू किया गया है ।

उपर्युक्त रणनीति के अंतर्गत भारत में CPI-Ns पर आधारित मुद्रास्फीति को 4%($\pm$2.1) के दायरे में रखने की कोशिश की जाएगी ताकि देश में मूल्य स्थिरता को बनाए रखा जा सके और आवश्यक उम्मीदों को नियंत्रित किया जा सके । यह ध्यान देने योग्य है कि मूल्य स्थिरता से दीर्घकाल में वृद्धि को बढावा मिलता है क्योंकि लोग आसानी से निर्णय कर सकते हैं ।

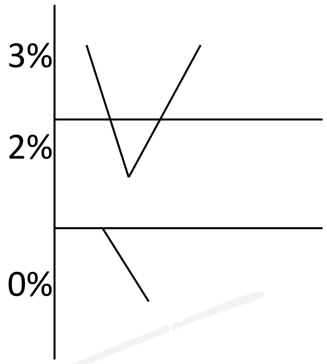

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की आई.टी. लचीली है ना कि अनम्य।

आलोचनात्मक मूल्यांकन :-

भारत में आई.टी. की रणनीति का लागू होना एक महत्वपूर्ण आर्थिक कदम है । इससे देश में दीर्घकाल में वृद्धि को बढावा मिलेगा । इस नीति के लागू होने से मौद्रिक नीति का निर्माण अधिक अनुशासन में आएगा। मौद्रिक नीति में पारदर्शिता एवं जवाबदेही उत्पन्न होगी ।

उपर्युक्त के बावजूद इस नीति के संचालन में निम्न बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती -

1. भारत की मुद्रास्फीति मुख्यतः लागत धक्का प्रकार की है ऐसी स्थिति में रेपो रेट की बदलाव सफलता को सीमित रखते हैं ।

2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में बडी मात्रा में मौद्रिक लेनदेन होते हैं ऐसी स्थिति में रेपो दर में बदलाव करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना कठिन होगा ।

3. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत के बैंक रेपो रेट में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ग्राहकों से वसूली की जाने वाली ब्याज दर में परिवर्तन नहीं करते ।

4. भारत में आर.बी.आई. पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं है तथा एम.पी.सी.ई. के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ।
   अगले 5 वर्ष हेतु आई.टी. का लक्ष्य भी सरकार द्वारा तय किया गया है । अतः आई.टी. की रणनीति पूर्ण रूप से राजनीति से मुक्त नहीं हो सकी है ।

राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद

National income & Product

प्रस्तावनाः-

अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। अर्थशास्त्र एवं किसी अर्थव्यवस्था की समझ के लिए राष्ट्रीय आय की गणना से जुडी अवधारणों का स्पष्ट होना आवश्यक है। वैसे तो इसका पता सामान्य तौर पर देश और वहां के लोगों की खुशहाली और उनकी प्रसन्नता से लगाते है। यह तरीका आज भी इस्तेमाल होता है हालाँकि हम यह जान चुके है कि आय से किसी भी समाज के बेहतर और कुशल होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस राय के पीछे कई वजहें भी हैं, जब 1990 के शुरूआती सालों में मानव विकास सूचकांक की शुरूआत हुई। इस सूचकांक में किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय को काफी प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तभी बेहतर होती है जब इन क्षेत्रों में भी बडे पैमाने पर निवेश किया जाता हो। यही वजह है कि विकास या मानव विकास का केंद्र बिंदु आय को माना जाता है।

अर्थात् -

- किसी देश में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, अर्थात् अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है।

सकल घरेलू उत्पाद **(GDP) :-** एक वित्त में किसी देश के निवासियों द्वारा देश की आर्थिक सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जी.डी.पी. कहलाता है।

अंतिम वस्तु एवं सेवा-

- उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आने वाली वस्तुएँ दो प्रकार की होती है।
  (1) मध्यस्थ वस्तुएँ- ऐसी वस्तुएँ जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में काम में ली जाती हैं, मध्यस्थ वस्तुएँ कहलाती है अर्थात् यह वस्तुएँ अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग में नहीं ली जाती। जैसे- कार का इंजन।

  (2) अंतिम वस्तुएँ - ऐसी वस्तुएँ जिनका उपभोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है अर्थात् इनमें उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है और उत्पादन संभव नहीं होता है। अन्तिम वस्तुएँ कहलाती है। जैसे - कार
- दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यस्थ वस्तुओं को छोड दिया जाता है और केवल अंतिम वस्तुओं को लिया जाता है।
  भारत की जी.डी.पी. गणना अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुरूप बनाने के लिए इसे सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) आधारित बनाया गया।

  (1) GVA_{fc} = Rent + Interest + Wages + Profit

  (2) $GVA_{bp} = GVA_{fc} +$ उत्पादन कर - उत्पादन सब्सिडी

  (3) $GDP_{mp} = GVA_{bp} +$ उत्पाद कर - उत्पाद सब्सिडी

- वह मूल्य जिस पर सरकार द्वारा अंतिम उपभोक्ता से कर वसूले जाते है, आधार मूल्य कहलाता है।

वित्त वर्ष :-

- 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने की अवधि वित्त वर्ष कहलाती है ।
- वित्त वर्ष को परिवर्तित करने की संभावना ढूंढने के लिए निम्न कमेटियों का गठन किया गया ।
  (1) बेल्बी आयोग
  (2) एल.के. झा समिति
  (3) दार्निश वाचा समिति
  (4) शंकर आचार्य समिति (हाल ही में निर्मित)

उत्पादन कर – उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगने वाला कर । जैसे- कच्चे माल पर लगने वाला कर
उत्पादन सब्सिडी- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मिलने वाली सब्सिडी उत्पादन सब्सिडी कहलाती है । जैसे- स्वदेशी कच्चे माल पर सब्सिडी
उत्पाद कर- अंतिम उत्पाद कर प्रति इकाई पर लगाया जाने वाला कर । जैसे-उत्पाद शुल्क, गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स आदि । यह कर अंतिम उपभोक्ता से वसूला जाता है जबकि उत्पादन कर उत्पादक से लिया जाता है ।
उत्पाद सब्सिडी – अंतिम उत्पाद पर उपभोक्ता को दी जाने वाली सब्सिडी जैसे – बैट्री कार पर सब्सिडी ।

जीडीपी के विभिन्न उपयोग निम्न है :-

1. जी.डी.पी. में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (वृद्धि दर) है जैसे – किसी देश की जी.डी.पी. रू. 107 है और यह बीते साल से रू. 7 ज्यादा है तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत है । जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकॉनोमी कहते है तो मतलब यह होता है कि देश की आय परिमाणात्मक रूप से बढ रही है ।
2. यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है । इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है । लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नही चल पाता है ।
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है ।

शुद्ध घरेलू उत्पाद **(NDP)** :-

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से मूल्य ह्रास घटाकर इसकी गणना की जाती है ।
- विभिन्न देशों में मूल्य ह्रास की गणना अलग-अलग विधियों से की जाती है । इसलिए शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार प्रत्येक देश में समान नहीं होता ।
- इस कारण शुद्ध घरेलू उत्पाद का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है ।

अन्य शब्दों में :-

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP), किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है, जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है । वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है जिसका मतलब उस सामान का घिसने (Depreciation) या टूटने-फूटने से होता है । इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है । भारत में यह फैसला केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है । यह एक सूची जारी करता है जिसके मुताबिक विभिन्न उत्पादो में होने वाली मूल्य कटौती (घिसावट) की दूरी तय होती है ।
इस तरह से देखें तो NDP = GDP – घिसावट

ऐसे जाहिर है कि किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस साल की जीडीपी से कम होगी। अवमूल्यन की शून्य करने का कोई भी तरीका नही है। लेकिन मानव समाज इस अवमूल्यन को कम से कम करने के लिए कई तरकीबें निकाल चुका है।

मूल्य ह्रास :- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन में प्रयोग में ली गई सम्पत्तियों व मशीनों में घिसावट होती है, इस कारण इनके मूल्य में आयी कमी मूल्य ह्रास कहलाती है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद का अलग-अलग प्रयोग निम्न है :-

(1) घरेलू इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले नुकसान को समझने के लिए किया जाता है। इतना ही नही खास समयावधि के दौरान उद्योग धंधे और कारोबार में अलग-अलग क्षेत्र की स्थिति का अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है।

(2) अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है ? इसकी वजह है कि दुनिया की अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएँ अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग-अलग दरें निर्धारित करती हैं। यह दर मूल रूप से तार्किक आधार पर तय होती है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (**GNP**) :-

किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) उस आय को कहते है जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोडकर हासिल होता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। या,

सकल राष्ट्रीय उत्पाद **(GNP)** :- एक वित्त वर्ष के दौरान देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है।

(1) $GNP_{mp} = GDP_{mp}$ + Net factor Income from abroad (NFIFA)

(2) NFIFA = Income of Indian Citizen outside India – Income earned by foreigner in India

विदेशों से होने वाली आय में निम्नांकित पहलू शामिल हैं :-

1. निजी प्रेषण (Private Remittances)
2. विदेश कर्जे पर ब्याज (Interest of The External Loans)
3. विदेश अनुदान (External Grants)

सामान्यतः फार्मूले के मुताबिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद $ विदेशों से होने वाली आय के बराबर है, लेकिन भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आमदनी के बदले हानि होती है। लिहाजा भारत का हमेशा विदेशों से होने वाली आमदनी के बराबर होता है

सकल राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न उपयोग निम्न प्रकार है –

i. इससे राष्ट्रीय आय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है । इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति तुल्यता (PPP) के आधार पर रैंक करता है ।
ii. राष्ट्रीय आय को आँकने के लिहाज से सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ-साथ गुणात्मक तस्वीरें भी पेश करता है । किसी भी अर्थव्यवस्था की आतंरिक के साथ-साथ बाहरी ताकत को भी बताता है ।
iii. यह किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में काफी मदद करता है । यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है ।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी (NNP) :-

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है, उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहते है ।

या

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद **(NNP)** :-

- इसकी गणना के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है ।
- भारत में कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय माना जाता है ।
- बाजार मूल्य/वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय को शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI) कहा जाता है ।
- $NNP_{mp} = GNP_{mp} -$ मूल्य ह्रास (Depreciation)
- $NNP_{fc} = NNP_{mp} -$ अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी
- प्रति व्यक्ति आय = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}} / \frac{NNP_{fc}}{\text{जनसंख्या}}$
- $GDP_{cp} = GDP_{mp} -$ मुद्रास्फीति (CP = स्थिर मूल्य)
- GDP_{cp} को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है ।
- बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को नाममात्र का सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है ।

  GDP Deflator = $\frac{\text{Nomial GDP}}{\text{Real GDP}} / \frac{GDPmp}{GDPcp}$

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न उपयोग निम्न प्रकार है :-

i. यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय (National Income) (NI) है । यद्यपि जी.डी.पी. , एन.डी.पी. और जी.एन.पी. सभी राष्ट्रीय आय ही है लेकिन नेशनल इनकम (NI) के तौर पर नहीं लिखा जाता ।
ii. यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आंकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ।
iii. जब हम NNP को देश की कुल आबादी से भाग देते है । तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है, यह प्रतिव्यक्ति सालाना आय होती है, यहाँ एक मूल बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है । ऐसे में किसी देश में मूल्य कटौती की दर ज्यादा होने पर प्रति व्यक्ति की आय में कमी होती है ।

- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संघठन द्वारा की जाती है ।
- राष्ट्रीय आय के लिए आकडों का संकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और केन्द्रीय सांख्यिकी संघठन (CSO) द्वारा किया जाता है ।
- यह दोनों संस्थाएँ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के अन्तर्गत कार्य करती हैं ।

  (1) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MOSPI = Ministry of Statistics & Program Implementation)

  (2) राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन (NSSO = National Sample Survey Office/Organization)

- राष्ट्रीय आय की गणना चार मूल्यों पर आधारित होती है ।
  (1) कारक लागत
  (2) <u>बाजार मूल्य</u> – वह मूल्य जिस पर अंतिम उपभोक्ता द्वारा वस्तुएँ खरीदी जाती है बाजार मूल्य कहलाता है । इसे वर्तमान मूल्य भी कहा जाता है ।
  (3) <u>आधार मूल्य</u> –
    - राष्ट्रीय आय की तुलना के लिए किसी एक वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है ।
    - भारत में 2011–12 को आधार वर्ष घोषित किया गया है ।
    - किसी वस्तु का आधार वर्ष का मूल्य आधार मूल्य कहलाता है ।
  (4) <u>स्थिर मूल्य</u>–
    - यदि बाजार मूल्य में से मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दिया जाये तो वह स्थिर मूल्य कहलाता है ।
    - राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न अवधारणाएँ प्रचलित है– सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल देशीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

<u>मौद्रिक राष्ट्रीय आय (Nominal National Income)</u>

इसे प्रचलित या चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय (National Income at Current Price) भी कहा जाता है। इसमें आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में उत्पादन को लेकर वस्तुस्थिति का पता नहीं लग पाता । अतः इस राष्ट्रीय आय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता ।

इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है–

$$GNP\ Deflator = \frac{Nominal\ GNP}{Real\ GNP}$$

GNP Deflator – सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिकारक
Nominal GNP – नाममात्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद
Real GNP – वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद

यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिकारक को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त करना हो तो इसके मूल्य को 100 से गुणा कर दिया जाता है । उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिकारक का मूल्य 1.25 हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा एवं इसका मान 125 आ जाएगा । इसका अभिप्राय यह होगा कि चालू मूल्य पर जीएनपी वास्तविक जीएनपी के मूल्य का 125% होगा ।

संवृद्धि एवं विकास (Growth and Development)

संवृद्धि (Growth) मात्रात्मक होती है तथा राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है । विकास गुणात्मक तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है ।

जीवन के अच्छे गुणवत्ता में आय अथवा ग्रोथ की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । लेकिन आय अथवा ग्रोथ द्वारा जीवन की गुणवत्ता को पूर्ण स्पष्ट नहीं किया जा सकता है । कुछ अन्य बातों की आवश्यकता होती है जैसे – ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य आदि ।

जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life)

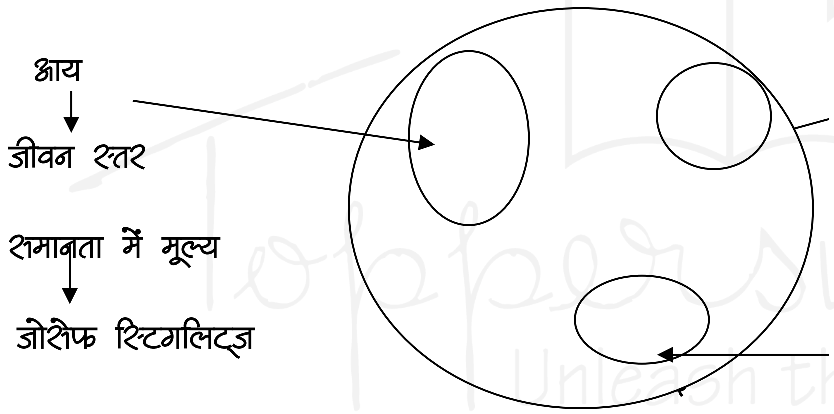

संवृद्धि तथा विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं है । यह एक-दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे- यदि एक राष्ट्र में अच्छी संवृद्धि है तो उसमें कर संग्रह का स्तर ऊँचा होगा, जिसके द्वारा संबंधित सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य पर सामाजिक व्यय बढा सकती है ।

इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक रिसर्च के अनुसार यदि साक्षरता की दर को 20% से बढा दिया जाता है तो संबंधित राष्ट्र की संवृद्धि दर में 5% तक की बढोतरी हो सकती है ।

मानव विकास सूचकांक HDI (Human Development Index)

विकास गुणात्मक होता है इसलिए उसे गणितीय रूप से नहीं मापा जा सकता है लेकिन मोटे रूप में इसकी स्थिति एवं दिशा को समझने के लिए यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया जाता है ।

मानव विकास सूचकांक के निर्माण में पाकिस्तान के स्वर्गीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब उल हक की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । हालाँकि उनके लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन की वास्तविक गरीबी की संकल्पना प्रेरणा का स्रोत रही है । प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार क्षमताओं का अभाव गरीबी है । उनके अनुसार विकास स्वतंत्रता प्रदायक होता है और एक क्षमतावान व्यक्ति ही स्वतंत्र हो सकता है ।

मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्न आयामों तथा सूचकों का प्रयोग किया जाता है।

1- आयाम **(Dimension)** सूचक **(Indicators)**
दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन — जीवन प्रत्याशा (Life Expeciancy) 168 वर्ष

2. ज्ञान
स्कूल के औसत वर्ष (Mean years of schooling) (5.4 वर्ष)
स्कूल के प्रत्याशित वर्ष (11.7 वर्ष)

3. जीवन स्तर:– वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय (Real per capita GNI)
यू.एस.डी. (संयुक्त राज्य) (USD: United State)
Dollors: PPP
आधार : $5497

नोट :-

1. <u>सकल राष्ट्रीय आय GNI (Gross National Income)-</u>
को निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग–

GNP_{mp} = Indirect taxes + Subsidy

GNP_{fc}= GNI

2. यह ध्यान देने योग्य है कि 2010 से पहले UNDP द्वारा GDP_{fc} का प्रयोग किया जाता था लेकिन 2010 में यूएनडीपी द्वारा यह कहा गया कि भूमंडलीकरण के कारण कई राष्ट्रों का जीवन स्तर विदेशी साधन आय से प्रभावित हो रहा है। इसलिए विदेशी साधन आय का ध्यान रखना जरूरी है। अतः उसके द्वारा 2010 में जी. एन. आई. के प्रयोग को शुरू कर दिया गया।

3. विनिमय दर (Exchange Rate) दो प्रकार की होती है।
– चालू–विनिमय दर।
– क्रय शक्ति आधारित विनिमय दर।

चालू विनिमय दरें मुद्राओं की क्रय शक्ति में अंतर को ठीक से प्रदर्शित नहीं कर पाती। जैसे – अमेरिकन डॉलर की माँग केवल उसकी क्रय शक्ति को लेकर नहीं होती है। उसकी माँग निवेश एवं अन्य कारणों से भी होती है, जिसके चलते उसकी विनिमय दर काफी ऊँची जा सकती है। ऐसी अवस्था में क्रय शक्ति आधारित विनिमय दर का प्रयोग अधिक उपर्युक्त होता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि यू.एन.डी.पी. द्वारा शामिल किए जाने वाले सभी राष्ट्रों की सकल राष्ट्रीय आय को अमेरिकन डॉलर्स में बदला जाता है।